बजट की ब्रांडिंग थी, ''ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया''

पर बजट के विरोध में युवा सड़कों पर संघर्षरत और कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं

जयपुर, 15 फरवरी (का.प्र.)। राजस्थान के बजट को लेकर इस बार प्री ब्रांडिंग का काम चला और मीडिया से लेकर सड़कों तक बजट का प्रचार किया गया तथा कहा गया कि इस बार ऐसा बजट होगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। पर हुआ इसके विपरीत, जिस तरह से बजट के बाद युवाओं से लेकर कर्मचारी संगठनों तक ने मोर्चा खोला है,उससे लग रहा है कि या तो ब्रांडिंग में कुछ ज्यादा बता दिया गया है या फिर बजट में ही कमी रह गई है। ऐसे में कांग्रेस जिस बजट पर आस लगाकर विधानसभा चुनाव में फिर से जीत की बात कर रही है, वह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है।

दरअसल बजट में आधारभूत ढांचे को लेकर बड़ी घोषणाएं की गईं है, जिनमें सड़क, बिजली, पानी ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें अब जनता कोई तवज्जो नहीं देती, क्योंकि हर सरकार सड़क, बिजली और पानी को लेकर काम करती ही है।

जनता को तो तत्कालीन परिस्थितियों में क्या चाहिए, इस बात को ज्यादा तवज्जो देती है। ऐसे में भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी घोषणाएं कर दी हो, लेकिन यह भी तय है कि इतनी बड़ी घोषणाओं का 6 महीने में धरातल पर आना नामुमकिन है, क्योंकि बजट पेश किए जाने के बाद सबसे जरूरी बात यह होती है कि वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे और जिस तरह की घोषणा की गई है, उनके लिए बजट जुटाया जाना कोई आसान काम नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार बजट युवाओं को समर्पित होगा, लेकिन सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें छला है और बजट घोषणा में कहीं भी भर्तियों का मामला सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं पहले से जो भर्तियां हुई हैं और लोगों की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, उसे लेकर पहले से ही गुस्सा है। वहीं राजस्थान में 4 साल में 16 से 17 पेपर लीक की घटनाएं भी सरकार और युवाओं के बीच में बड़ी खाई पैदा कर चुकी है। इसलिए जिस बजट को युवाओं का बजट बताकर सरकार ब्रांडिंग कर रही थी, वह ब्रांडिंग खरी उतरती नहीं दिख रही है।

राज्य सरकार के मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक बार यह कहते रहे हैं कि उन्हें 2003 में कर्मचारियों ने चुनाव हराया था और हम उनकी बात नहीं समझ सके थे, लेकिन इस बार कहीं भी एंटी इनकंबेंसी नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर बजट सामने आने के बाद कर्मचारी संगठनों के धरने - प्रदर्शन और चेतावनी के ज्ञापन बता रहे हैं कि कर्मचारी इस बार भी सरकार से नाखुश हैं। राज्य के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन ने तो राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है।

- **बिजली, पानी, सड़क आदि की इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी बड़ी घोषणाओं से जनता अप्रभावित लगती है। इन घोषित बड़े प्रोजैक्ट की शुरूआत 6 महीने में होना नामुमकिन ।**
- **इसके बावजूद बजट की प्री ब्रांडिंग के बाद अब पोस्ट ब्रांडिंग पर सरकार का पूरा फोकस है।**
- **मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकारों पर प्रोजैक्ट रोकने का आरोप लगाया तो भाजपा ने द्रव्यवती सौंदर्यीकरण योजना को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया।**
- **मैट्रो प्रोजैक्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह तो कांग्रेस सरकार की अपनी योजना थी, पर सरकार उदासीन दिख रही है।**

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 दिन पहले ही बारां दौरे के दौरान कहा था कि भाजपा सरकार हमारी योजनाओं को रोक देती है और यह परंपरा ठीक नहीं है। इस बात पर खुद मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की योजनाओं पर ब्रेक नहीं लगाया।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण जयपुर में द्रव्यवती नदी का दिया जा रहा है। पिछली भाजपा सरकार के समय जयपुर के मध्य से गुजर रही द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, इसका पूरा काम बंद कर दिया गया और आज हजारों करोड रुपए का यह प्रोजेक्ट गंदे नाले में तब्दील होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं खुद कांग्रेस सरकार की जयपुर के लिए बनी बड़ी योजना मैट्रो प्रोजेक्ट को सरकार आगे बढ़ाने में विफल साबित हो रही है। अब तक मेट्रो के पहले 2 फेज ही बन पाए हैं। कहा जा रहा है कि जो सरकार अपनी योजना को ही धरातल पर नहीं ला पा रही है,वह भाजपा सरकार की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ा सकती है।

अब बजट पेश किए जाने के बाद में भी इसकी खूब मार्केटिंग हो रही है और होर्डिंग - पोस्टर और मीडिया में विज्ञापन में यह सब देखा जा सकता है। इस मार्केटिंग के उलट लोकसभा में राहुल गांधी हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो यहां भाजपा को बैठे-बिठाए मुद्दा मिल गया है कि आखिरकार क्या कारण रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को यहां बुलाकर हजारों बीघा जमीन आवंटित कर दी। राज्य विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष से लेकर भाजपा के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि वह राहुल गांधी के साथ हैं या अडानी के साथ। ऐसे में जिस मुद्दे पर पूरे देश में कांग्रेस अडानी के खिलाफ खड़ी है, वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अडानी को जमीन दिया जाना कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल रहा है। ऐसे में अब जब मार्च के दूसरे सप्ताह में विधानसभा का सत्र समाप्त होगा। उसके बाद में राज्य में पूरी तरह से राजनीतिक दल चुनावी मुद्रा में आ चुके होंगे। इस स्थिति में जहां मुद्दों को लेकर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, वही राजस्थान कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष पार्टी के लिए चुनावी वर्ष में नुकसान का सौदा होता दिख रहा है।

चीन सीमा पर सात और नई बटालियन तैनात होगी

नई दिल्ली, 15 फरवरी। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को चित्त कर देने के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तौर पर चीन सीमा पर चप्पे-चप्पे पर सैनिकों की तैनाती के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) के 7 नए बटालियन के गठन का ऐलान किया है। देश में पहली बार 24 अक्टूबर 1962 को आई.टी.बी.पी. का गठन किया गया था। आरंभ में इसकी सिर्फ 4 बटालियन थी। मौजूदा वक्त में इसकी 45 पलटनें और 4 विशेष पलटनें हैं। अब 7 नई बटालियान का गठन होने से एल.ए.सी. के हर एक प्वाइंट पर सैनिकों की तैनाती हो सकेगी। इससे अतिसंवेदनशील इलाकों में सेना की गश्त बढ़ जाएगी। साथ ही चीन पर 24 घंटे बारीकी से नजर रखना और गुस्ताखी करने पर उन्हें तत्काल मुंहतोड़ जवाब देना काफी आसान हो जाएगा।

मंत्रालयिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर कलैक्ट्रैट आए, जहाँ सभा का आयोजन हुआ। उसके पश्चात सैकड़ों मंत्रालयिक कर्मचारियों ने प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी के नेतृत्व में बजट घोषणा की प्रतियाँ जलाई एवं सभा स्थल से जिला कलेक्टर कार्यालय के गेट पर पहुँच कर नारेबाजी करते हुए प्रशासन के बुलावे पर महासंघ के 21 प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर जिला अध्यक्ष मुकेश मुदगल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी ने कहा कि यदि सरकार द्वारा अभी भी मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगो पर आगामी समय में निर्णय नहीं किया, तो आंदोलन को तेज करते हुए जयपुर में 9 मार्च से महापड़ाव डाल दिया जायेगा।

मासलपुर वन क्षेत्र में मिला टाइगर का शव

करौली, 15 फरवरी (नि.स.)। मासलपुर वन क्षेत्र में ठेकड़ा गौशाला के पास टाइगर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। टाइगर का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और पुलिस दल घटनास्थल पर पहुँचे।

वन विभाग की टीम ने क्षेत्र का मौका मुआयना कर घटनाक्रम की जानकारी ली। बाद में मृत टाइगर के शव को करौली लाया गया। मैडीकल बोर्ड से कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के बाद उसका उच्च अधिकारियों के उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया। पोस्टमार्टम के बाद ही टाइगर की मौत के वास्तविक कारणों का पता लग सकेगा।

- **वन विभाग करौली के मासलपुर वन क्षेत्र ठेकड़ा गौशाला के पास टाइगर का शव मिलने की सूचना मिली थी, शव को करौली लाया गया है।**
- **उप वन संरक्षक ने बताया कि शव 4-5 दिन पुराना लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता लगाया जा सकेगा।**

करौली के मासलपुर के जंगलों से टाइगर का 4-5 दिन पुराना शव बरामद हुआ है।

भू संरक्षण उप वन संरक्षक सुरेश मिश्रा ने बताया कि, मासलपुर वन क्षेत्र में ठेकड़ा गौशाला के पास जंगल में एक टाइगर का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रथम दृष्टया टाइगर का शव 4 से 5 दिन पुराना लग रहा है। टाइगर के पग मार्क और धारियों के सैम्पल विशेषज्ञ टीम के पास भेजे गए हैं। जिसके आधार पर टाइगर की पहचान की जाएगी। टाइगर का करौली में पोस्टमार्टम कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार प्रातः उस इलाके से कुछ महिलाएं निकली तो उन्हें वन्यजीव मृत दिखाई पड़ा। इसके बाद सूचना पर वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इधर जिला कलैक्टर अंकित कुमार सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए टाइगर के पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार के समय उपस्थित होने के लिए करौली उपखण्ड अधिकारी दीपांशु सागवान को अधीकृत किया है।

लूणकरनसर के मलकीसर बड़ा गांव में हिरण का शिकार

बीकानेर, 15 फरवरी (कासं)। जिले के लूणकरनसर स्थित मलकीसर बड़ा गांव के सूनसान खेत में हिरण का शिकार कर उसके मांस को बाजार में बेचने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुछ युवकों ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को पकड़ लिया। उन्होंने हिरण का बचा कुचा शव भी मौके से बरामद किया।

- **इस संबंध में एक युवक को पकड़ा गया और हिरण का शव भी बरामद किया गया।**

मलकीसर बड़ा में देर रात हुई इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय युवकों की टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह राठौड़ अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने हिरण के शिकारी को पकड़ा व वन विभाग टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने युवक तथा हिरण के शव को कब्जे में ले लिया। महिपाल सिंह राठौड़ के अलावा राजू कायल, रविन्द्र बिश्नोई, चंद्र पाल बिश्नोई, वन विभाग टीम के लेखराम गोदारा, वीरेंद्र बेनीवाल, विजयपाल, सुशीला कुमारी ने इस कार्यवाही में सहयोग दिया।

पता चला है कि, शिकार रोकने और शिकारियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी जिस वन विभाग के पास है, उसकी गाड़ी शिकारियों का पीछा करते हुए रास्ते में खराब हो गई। बाद में टाइगर फोर्स टीम की गाड़ी से शिकारियों का पीछा कर एक शिकारी को पकड़ा गया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि शिकार इसी एक युवक ने किया था या फिर कुछ और शिकारी भी इसमें शामिल थे।

बताया जाता है कि शादियों के सीजन में हिरण के शिकार की घटनाएं अधिक होती हैं। इस काम में एक जाति विशेष के लोगों पर प्रायः शिकार का शक किया जाता है।

लॉरैंस विश्नोई को पंजाब से जयपुर लाया गया

जयपुर, 15 फरवरी (कासं)। राजधानी के जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब पर फायरिंग व रंगदारी मांगने के मामले में जयपुर पुलिस ने बुधवार को एक बार फिर से लॉरैंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से गिरफ्तार किया है। देर शाम को पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद गाड़ी से लेकर जयपुर पहुंची।

जवाहर सर्किल थानाधिकारी सुरेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि, लॉरैंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने के लिए बुधवार सुबह जयपुर कमिश्नरेट पुलिस पंजाब पहुंची थी। प्रोडक्शन वारंट लेकर पंजाब जेल से उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे चंडीगढ़ से बख्तरबंद गाड़ी में सात कमाण्डो के साथ बिठाया गया। बख्तरबंद गाड़ी के आगे-पीछे पुलिस जवानों की चार गाड़ियां भी पंजाब से जयपुर आईं। शाम करीब साढ़े सात बजे पुलिस लॉरैंस बिश्नोई को लेकर जयपुर पहुंची, जहां उसे जवाहर सर्किल थाने में रखा गया।

अडानी के खिलाफ तीसरी याचिका की सुनवाई शुक्रवार को

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस बात के लिये तैयार हो गया कि वह मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता द्वारा दायर की गई याचिका का परीक्षण शुक्रवार को करेगा। इस याचिका में माँग की गई है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुये अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जाँच की जाये। याचिका में कहा गया है कि इसके साथ ही, ग्रुप के एफ.पी.ओ. में कथित रूप से ''जनता के पैसे की बहुत बड़ी राशि'' के निवेश के मामले में एल.आई.सी. तथा एस.बी.आई. की भूमिका की भी जाँच की जाये।

कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से प्रस्तुत वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली

- **सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की कम्पनियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।**

बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल थे, के समक्ष इस याचिका की अति शीघ्र सुनवाई की माँग की। शुरु में, बैंच ने कहा था कि वह इस प्रकरण को 24 फरवरी को लेगी लेकिन जब वकील ने कहा कि इसी प्रकरण से संबंधित दो अन्य पी.आई.एल. शुक्रवार के लिये सूचीबद्ध हैं तो बैंच ने इस प्रकरण को भी उसी दिन लेने का निर्णय ले लिया।

ठाकुर द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, खासतौर से इसके चेयरमैन तथा उनके सहयोगियों की जाँच के निर्देश दे, जिन्होंने जनता के तथा सरकारी कोष के लाखों-करोड़ रू. ऐंठ लिये हैं। याचिका में कहा गया है कि यह जाँच सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवारत जज की देखरेख तथा मॉनिटरिंग में विभिनन जाँच एजेंसियों, जैसे सी.बी.आई., ई.डी., डी.आर,आई, सी.बी.डी.टी., ई.आई.बी., एन.बी.बी., एस.ई.बी.आई., आर.बी.आई. तथा एस.एफ.आई.ओ. से कराई जाये।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित एडवोकेट विशाल तिवारी तथा एम.एल. शर्मा द्वारा दायर पी.आई.एल. अदालत के पास पहले से मौजूद हैं। जया ठाकुर की याचिका की सुनवाई भी इन्हीं दो पी.आई.एल. के साथ की जायेगी।

अब आसाम व महाराष्ट्र में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा एन.सी.पी. के नेता शामिल है, में इस बात को लेकर नाराजगी है तथा वे एकनाथ शिंदे सरकार पर आरोप लगाते हुये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार ने, सत्ता में बने रहने के लिये, भाजपा के साथ गुप्त समझौता कर लिया हैं एन.सी.पी. नेता सुप्रिया सुले ने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट में कहा, ''क्या भाजपा नेतृत्व महाराष्ट्र के लिये कुछ भी नहीं छोड़ने का निर्णय ले चुका है? इससे पहले, वे महाराष्ट्र के बिजनेस और रोज़गार को ले गये थे। अब वे हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को ले जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी निवेश परियोजनाओं को गुजरात तथा अन्य राज्यों में ले जाने को लेकर विपक्ष एकनाथ शिंदे सरकार की कड़ी आलोचना करता आ रहा है। वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजैक्ट जो योजनानुसार, मूल रूप से महाराष्ट्र में आना था, को गत वर्ष गुजरात ले जाया गया तथा यही हश्र टाटा एयरबस प्रोजैक्ट का हुआ था। कुछ सप्ताह बाद, घोषणा की गई कि कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन के फ्रांसीसी निर्माता, सफ्रान ने इस प्रोजैक्ट को नागपुर से हैदराबाद ले जाने का निर्णय ले लिया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता सचिन सावंत इसको लेकर बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा, ''उद्योगों को छोड़िये। भाजपा भगवान शिव को भी महाराष्ट्र से छीन लेना चाहती है। हम असम सरकार के इस अनर्गल दावे की कड़ी भर्त्सना करते हैं कि छठा ज्योतिर्लिंग उस राज्य में स्थित है। हम मांग करते हैं कि शिंदे-फड़नवीस सरकार अपना रुख स्पष्ट करे तथा असम की भाजपा सरकार की इस अति उत्साहपूर्ण कार्यवाही की तथा इसकी साफ तौर पर निन्दा करे क्योंकि इससे महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों की भावनाएं तथा सभी भारतवासियों की आस्था आहत हुई है। महाराष्ट्र के प्रति भाजपा का वैमनस्य एक बार फिर दिखाई दिया है।'' शिव सेना यू.बी.टी. नेता आदित्य ठाकरे ने असम सरकार के इस दावे को स्तब्धकारी बताया है। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस संबंध में एक बयान जारी करें। जहां भाजपा तथा शिंदे गुट के नेता अधिकांशतः इस मामले में चुप्पी साधे रह रहे हैं, वहीं भाजपा विधायक राम कदम ने डैमेज़ कंट्रोल की कोशिश करते हुये कहा है कि विपक्षी नेता एक अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि भीमा शंकर महाराष्ट्र में स्थित है।

'नारे लगाकर और कार्यवाही में बाधा डालकर कोई भी श्रेष्ठ विधायक नहीं बन सकता'

लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला ने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा

गांधीनगर, 15 फरवरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

गुजरात के मुख्य मंत्री, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल; गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष, श्री शंकर चौधरी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद थे।

इस अवसर पर बिड़ला ने कहा कि गुजरात की 15वीं विधान सभा युवाशक्ति और अनुभव का अनूठा मेल है। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि विधान सभा में 82 नवनिर्वाचित सदस्य हैं और 15 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जिनमें से 8 पहली बार सदस्य बनी हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए, बिड़ला ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन पर मतदाताओं की समस्याओं के समाधान की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए विधानमंडलों में चर्चा और संवाद होना चाहिए और चर्चा का स्तर उच्चतम स्तर का होना चाहिए। बिड़ला ने कहा कि राज्य विधान सभाओं में चर्चा और संवाद का स्तर जितना ऊंचा होगा, कानून उतने ही बेहतर बनेंगे।

पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए बिड़ला ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सदन की गरिमा बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। सदनों में चर्चा के स्तर में गिरावट और सदन की गरिमा में गिरावट हमारे लिए चिंता का विषय है। एक उत्कृष्ट विधायक वही होता है जो उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण चर्चा और संवाद में भाग लेता है और सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। सदस्यों को तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि निराधार आरोपों पर आधारित तर्क लोकतंत्र को कमजोर करते हैं।

- **बिड़ला ने कहा, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक, रचनात्मक और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए।**
- **बिड़ला ने यह भी कहा कि, सदस्यों को अपनी बात तथ्यों के साथ रखनी चाहिए। निराधार आरोपों पर आधारित तर्क लोकतंत्र को कमजोर करते हैं।**
- **इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी विधायक मौजूद थे।**

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, बिड़ला ने कहा कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक, रचनात्मक और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली चाहिए। लेकिन जिस तरह सुनियोजित तरीके से सदनों की कार्यवाही में बाधा डालकर सदनों का कार्य स्थगित करने की परंपरा डाली जा रही है, वह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन में चर्चा, वाद-विवाद, असहमति हो, लेकिन सदन में गतिरोध कभी नहीं होना चाहिए।

कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि गुजरात की जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संसदीय कार्यप्रणाली, नियमों एवं सदन की कार्यवाही से परिचित हों और अपने कर्तव्यों का सुचारु रूप से पालन कर जनाकांक्षाओं पर खरे उतरे। इस उद्देश्य से इस विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का समापन 16 फरवरी, 2023 को गुजरात के राज्यपाल, आचार्य देवव्रत के भाषण के साथ होगा।

गुजरात विधानमंडल के सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा गुजरात विधान सभा सचिवालय के सहयोग से किया जा रहा है।

बी.बी.सी....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को लेकर दो हिस्सों में बनाई गई एक डाक्युमैंट्री प्रसारित की थी। यह अलग बात है कि सत्तारूढ़ दल तथा आई.टी. विभाग के अधिकारियों ने अपने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया है कि इन अनुमानों और निष्कर्षों को दूर करने के पूरे-पूरे प्रयास किये जा रहे हैं कि यह बदले की कार्यवाही है, कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठान को नोटिस भेज दिये गये थे लेकिन बी.बी.सी. ने उनकी अनुपालना नहीं की थी। इस बीच, बी.बी.सी. (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन) ने अपने कर्मचारियों को भेजे गये एक ई-मेल में, प्रसारण विभाग के कर्मचारियों के अलावा, सब कर्मचारियों से कहा है कि अपने घर से ही काम करें। कर्मचारियों से कहा गया है, ''अगर कर्मचारियों से उनकी आय के बारे में पूछा जाता है तो वे चाहे तो उसका उत्तर न दें। उन्हें सिर्फ वेतन संबंधी प्रश्नों के उत्तर ही देने चाहिये।'' बी.बी.सी. ने अपने स्टाफ को सलाह दी है कि वे (आयकर) अधिकारियों के साथ सहयोग करें तथा पूरी समझदारी और विवेक के साथ प्रश्नों के उत्तर दें।''

सूत्रों ने बताया कि टैक्स अधिकारियों ने बी.बी.सी. के वरिष्ठ प्रबंधन से पूछताछ की तथा ''टैक्स'', ''बिल्स'', तथा ''ब्लैक मनी'' जैसे की-वड्‌र्स का प्रयोग करते हुये स्टाफ कम्प्यूटरों की सर्च की।'' सूत्रों ने कहा कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल फोनों की ''क्लोनिंग'' कर ली गई हैं।

टैक्स अधिकारी टैक्स-लाभ, टैक्स-चोरी, प्रॉफिट का महत्वपूर्ण डायवर्जन के आरोपों तथा बी.बी.सी. द्वारा नियमों की अनुपालना नहीं किये जाने की जाँच कर रहे हैं। सूत्रों ने जोर देते हुये कहा, ''बी.बी.सी. को नोटिस पहले ही भेज दिये गये थे, लेकिन उसने उनकी ''अवहेलना की तथा अनुपालना नहीं की।'' सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यह सर्वे ''एकाएक लिया गया निर्णय नहीं है'' तथा यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जो उस समय शुरु हुई, जब बी.बी.सी. ने टैक्स अधिकारियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के ''उत्तर नहीं दिये।''

''फिच'' पाकिस्तान रेटिंग, सी.सी. सी.+ से सी.सी.सी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुनर्संरचना एक बढ़ती हुई वास्तविक आशंका है। अगस्त 2021 के अंत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भण्डार सर्वाधिक 20 बिलियन डॉलर था जो फरवरी 2023 में करीब 2.9 बिलियन डॉलर रह गया।

घटता विदेशी मुद्रा भण्डार, करंट अकाउन्ट डैफिसिट (सी.ए.डी.) और विदेशी ऋणों का बकाया भुगतान एक बड़ी मात्रा में दर्शाता है, लेकिन लगता है कि देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय में पूर्व में किया गया हस्तक्षेप, खासतौर पर वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में जब एक्सचेंज रेट में एक अनौपचारिक सीमा तय की गई थी, वह अब तक लागू ही है।

फिच ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों व ऊर्जा सब्सिडीज़ में कमी और नीतियों के बाजार द्वारा तय एक्सचेंज रेट के अनुरूप ना रहने के कारण आई.एम.एफ. कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान के 9वें रिव्यू पर काम अटक गया है। यह रिव्यू नवम्बर 2022 में हो जाना चाहिए था। हम समझ सकते हैं कि इस रिव्यू को पूर्ण किया जाना अतिरिक्त अग्रिम राजस्व उपायों और बिजली व ईंधन की कीमतों का नियमन करने पर निर्भर है। राजनीतिक मोर्चे पर भी चुनौतियां हैं। फिच का मानना है कि बेल-आउट पैकेज उपलब्ध करवाने के लिए आई.एम.एफ. की शर्तें भारी आर्थिक गिरावट, उच्च महंगाई दर और पिछले वर्ष बाढ़ से हुई तबाही के मद्देनजर सामाजिक और राजनीतिक रूप से कठिन साबित हो सकती है। पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में आम चुनाव हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी पार्टी इन चुनावों में वर्तमान सरकार को चुनौती देगी, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ का आमंत्रण पहले ही ठुकरा चुके हैं। शरीफ ने उनसे आई.एम.एफ. की बातचीत सहित राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करने का राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करने का आग्रह किया था। इसके अलावा फण्डिंग को लेकर हाल ही आया दबाव देश के परम्परागत मित्र देश चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की प्रकट अनिच्छा को लेकर भी है।

इन देशों ने आई.एम.एफ. के किसी पैकेज में पाकिस्तान को ताजा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया है। यह सहायता भी अन्य देशों और द्विपक्षीय फण्डिंग के लिए महत्व रखती है। इस बीच, वैश्विक सामरिक विशेषज्ञों ने कहा है कि इस्लामी देशों में पाकिस्तान के मित्र भी अब यह मानने लगे हैं कि पहले उसे अपनी आंतरिक नीतियों को ही सही करने की जरूरत है और उसे चरमपंथी इस्लामी गुटों को अपने देश से कार्य संचालन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

पाकिस्तान को उसके निकट माने जाने वाले मुस्लिम मित्र देशों ने तगड़ा झटका दिया है। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान की सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह कश्मीर को भूल जाए तथा भारत से मित्रता कर इस विवाद को खत्म करे।

विशेषज्ञ कुल मिलाकर इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान के अंदरूनी तानाशाह हिल गए हैं और उन्हें यह नहीं सूझ रहा है कि उस राक्षस को कैसे नियंत्रित किया जाए जो उन्होंने आतंकवादी संगठन तहरीक ए तालिबान (टी.टी.पी.) के रूप में स्वयं ही खड़ा किया था। देश के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर में गत 30 जनवरी को हुई हुए आत्मघाती धमाके सहित हुए कई आतंकवादी हमले देश की आर्थिक परेशानियों को बढ़ाते रहे हैं। पेशावर के हमले में सौ से अधिक लोग मारे गए थे।

1.1 बिलियन डॉलर के फण्ड्स को जारी करने को लेकर पाकिस्तान सरकार की इन्टरनैशनल मॉनिटरी फण्डड (आई.एम.एफ.) के साथ हुई बातचीत के सकारात्मक परिणाम नहीं निकल हैं। इससे स्थिति के और बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है।

अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके एवं हडसन इन्स्टीट्यूट के सीनियर फैलो हुसैन हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आतंकवाद ने ब्लॉक कर दिया है और चीन पर उसकी अवास्तविक निर्भरता के कारण उस पर विदेश ऋणों का भारी बोझ है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहने वाली प्रवृत्ति का भी उल्लेखकिया और कहा कि देश को आय निर्मित करने के तरीकों के बारे में पता लगाना चाहिए। इक्कानी न कहा कि ''पाकिस्तान में बार-बार उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट का कारण उसका स्वयं में सुधार करने से इंकार करना है।

देश की राष्ट्रीय विचारधारा ने सैन्य व्यय को लगातार इतना बढ़ाया है कि उसे वहन करना मुश्किल है। जेहादी आतंकवाद ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ब्लॉक कर दिया है।'' उन्होंने आगे कहा कि ''अफगानिस्तान और भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंधों ने व्यापार की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। पाकिस्तान को समृद्ध बनने के लिए विवादित राजनीतिक अर्थव्यवस्था से परे जाने की जरूरत है, लेकिन यह फिलहाल दूर की कौड़ी प्रतीत होता है।''

भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) जे.जे. सिंह ने कहा कि, ''लगता है कि पाकिस्तान स्वयं को बर्बाद करने की कार्यवाही पहले ही कर चुका है।'' सिंह ने कहा कि स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण से बाहर हो रही है और हम यह नहीं जानते कि पाकिस्तान में फिलहाल किसकी तूती बोल रही है। उन्होंने कहा कि जब किसी परमाणु हथियार सम्पन्न देश में नेतृत्व का गंभीर संकट हो तो यह भारत सहित हर किसी के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त जी. पार्थसारथी ने कहा कि पाकिस्तान यदि संकट से उबरना चाहता है तो उसे आतंकवाद को प्रोत्साहन देना बंद कर सकारात्मक आर्थिक सहयोग पर फोकस करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ''पाकिस्तान कि समक्ष अब कूटनीति और रणनीति का एक अभूतपूर्व संकट है। इस्लामी दुनिया के उसके मित्र तक अब यह मान चुके है। कि पाकिस्तान को अपने घर को संभालने की जरूरत है और उसे अपनी भूमि तथा पड़ोस में चरमपंथी इस्लामिक गुटों और आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908